फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 74 संख्याः 343 प्रभात जयपुर, रविवार 14 जुलाई, 2024 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

ARBiT

Why His Films Will Run, Always...

"Teri aan baan shaan pe jahan qurban,
Tu hai veer, randhir, baanka Hind ka jawan!..."

Alternative Flours

Whether you're avoiding wheat gluten or simply curious about those small bags of bean flours in the baking aisle, here's an intro to alt flours.

'आप लोग लम्बी छुट्टी पर ना जायें, बहुत कुछ होने वाला है'

कांग्रेस के प्रवक्ता ने उपचुनावों के नतीजे आने के बाद पत्रकारों को सलाह दी

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 जुलाई। कांग्रेस तथा इण्डिया गठबंधन के लिए यह एक यादगार दिन है, जिन्होंने उपचुनावों में 13 में से 10 सीटें जीत ली हैं। भाजपा 2 सीटों पर विजयी रही है और 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी जीता है।

भाजपा को एक और प्रबल संकेत देते हुए, कांग्रेस ने उत्तराखण्ड की बद्रीनाथ सीट जीत ली है। कांग्रेस ने उत्तराखण्ड में दोनों सीटें जीती हैं तथा हिमाचल प्रदेश में 3 में से 2 सीटों पर उसे विजय मिली है।

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सभी चार उपचुनावों में विजयी रहीं, डी.एम.के. तमिलनाडू में जीती और बिहार में पप्पू यादव के नजदीकी माने जाने वाले एक निर्दलीय की जीत हुई है।

भाजपा ने हिमाचल प्रदेश में एक तथा मध्यप्रदेश में एक सीट पर विजय हासिल की है।

आम आदमी पार्टी पंजाब में जालंधर सीट पर विजयी रही, जिसे आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर माना जा रहा है।

- लोकसभा चुनावों के बाद, देश में हुए 13 उपचुनावों में 10 सीटों पर जीत दर्ज कराने के बाद, कांग्रेस पार्टी का मनोबल हिलोरें मार रहा है।
- कांग्रेस ने दावा किया कि अयोध्या के बाद बद्रीनाथ व अन्य धार्मिक सीटों पर जीत इस बात का द्योतक है कि अब धार्मिक नारे जनता को रास नहीं आ रहे हैं तथा चुनाव विशेषज्ञ प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव से पूर्व कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से भाजपा के वोटों में कुछ इजाफा नहीं होगा।
- बिहार में न तो लालू यादव की पार्टी जीती और न ही भाजपा-जे.डी. (यू) गठबंधन जीता, एक निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई जो पप्पू यादव के करीबी बताये जाते हैं।
- कांग्रेस ने भाजपा पर कटाक्ष किया कि आत्ममंथन करना चाहिए कि "ये गड़बड़ क्यों हो रहा है।"

लोकसभा चुनावों के तुरंत बाद आये उपचुनावों के परिणाम इण्डिया गठबंधन के लिए अच्छी खबर हैं और माना जा रहा है कि इससे इण्डिया गठबंधन का मनोबल बहुत बढ़ेगा।

कांग्रेस ने उपचुनाव के परिणामों को "भाजपा के मुँह पर थप्पड़" बनाते हुए कहा है कि भाजपा नेतृत्व को अपने अंदर झांककर देखना चाहिए, यह समझने के लिए कि गलत क्या हो रहा है।

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पत्रकारों से कहा है कि लंबी छुट्टी पर ना जाएं, बहुत कुछ होने वाला है। शायद वो यह संकेत देना चाहते हैं कि अगले कुछ महीनों में भाजपा सरकार के संदर्भ में कुछ भारी राजनीतिक डवलपमैंट हो सकते हैं। उनका इशारा शायद यह है कि मोदी सरकार के लिए बड़ा संकट पैदा हो सकता है।

चार राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और उनके परिणाम इस बात का संकेत होंगे कि हवा का रुख किधर है और क्या मोदी वाकई संकट में हैं।

कांग्रेस के अनुसार, अयोध्या, बद्रीनाथ तथा धार्मिक रूचि वाले अन्य स्थानों के चुनाव परिणाम स्पष्ट संकेत देते हैं कि राजनीतिक लाभ के लिए हिन्दूवाद के इस्तेमाल से मतदाता तंग आ गए हैं और अब वो हिन्दू मुसलमान मुद्दे से प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

जमीनी विवाद में रिश्तेदार की हत्या, बुजुर्ग को आजीवन कारावास

जयपुर, 13 जुलाई (का.सं.)। अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-6 महानगर द्वितीय ने जमीनी विवाद के कारण हुई रंजिश में रिश्तेदार की हत्या करने वाले बुजुर्ग अभियुक्त सगीर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने 72 वर्षीय इस अभियुक्त पर 20 हजार पांच सौ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने सजा की अवधि को तय करते हुए कहा कि, यह सही है कि अभियुक्त 72 साल की उम्र का है, लेकिन उसका अपराध समाज को आतंकित करने वाला है। ऐसे में उसे आजीवन कारावास देना उचित है।

- आरोपी सगीर अहमद ने जमीन के विवाद में अपने रिश्तेदार अयूब की हत्या कर दी थी। आरोपी 72 वर्षीय है पर अदालत ने कहा, उसका अपराध समाज को आतंकित करने वाला है।

अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र सिंह ने अदालत को बताया कि, घटना को लेकर मृतक के बेटे आमिर ने 11 जनवरी, 2022 को भट्टा बस्ती थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसके पिता अयूब का हमारे रिश्ते में दादा लगने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

इंडिया गठबंधन का कहना है, आपातकाल को राजनैतिक दृष्टि से भुनाने की नीति सफल नहीं हो पा रही भाजपा की?

आर.जे.डी., भाकपा व अन्य दलों ने सार्वजनिक रूप से कहा कि भाजपा इंडिया गठबंधन में फूट डालने का प्रयास कर रही है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 जुलाई। आपातकाल के भूत को बंद बोतल से बाहर लाकर "जैसे को तैसा" वाली भाजपा की रणनीति वर्तमान की राष्ट्रीय राजनीति में फिट बैठती प्रतीत नहीं होती क्योंकि प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने भाजपा के इस दृष्टिकोण को यह मानते हुए खारिज कर दिया है कि यह बेरोजगारी और मंहगाई सहित राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर बहस से बचने का जुगाड़ है।

भाजपा पर संविधान को पुनः लिखने और एक एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के आरक्षण को समाप्त करने को लेकर कांग्रेस और विपक्ष के प्रचार अभियान के एक सीधे पलटवार के रूप में भाजपा नेतृत्व वाली एन.डी.ए. सरकार ने अपने शासन के लगातार ग्यारहवें वर्ष में भी आपातकाल के भय को पुर्नजीवित किया है।

- इंडिया गठबंधन का यह भी मानना है कि आपातकाल में मुख्य रूप से पीड़ित होने वाले भी कह रहे हैं कि यह पुरानी बात हो गई है और इस समय उसे उठाना विपक्ष की एकता में दरार पैदा कर रहा है।
- शिव सेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि आपातकाल की घोषणा तब की गई थी जब रामलीला मैदान से, सेना के जवानों से सरकार के आदेश नहीं मानने की अपील खुलेआम की गई थी। तब राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण आपातकाल लगाया गया था।

नए सांसदों के शपथ ग्रहण के तुरन्त बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने एक प्रस्ताव का पठन किया था, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा करीब 50 वर्ष पूर्व लगाए गए आपातकाल की भर्त्सना की गई थी। अब गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें कहा गया है कि आपातकाल लागू किए जाने की तिथि 25 जून को "संविधान हत्या दिवस" के रूप में मनाया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि इस प्रकार के कदमों से नए वोटर्स की मनोस्थिति पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

इस मुहिम को शुरु करने के पीछे भाजपा का प्रकट उद्देश्य कांग्रेस को उसी की भाषा में जवाब देना और साथ ही इण्डिया गठबंधन की पार्टियों में फूट डालना है क्योंकि मुलायम सिंह यादव सहित विपक्ष के नेता आपातकाल के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प. बंगाल में चारों सीटें जीतीं तृणमूल कांग्रेस ने

लोकसभा चुनाव की रणनीति दोबारा अपनाई तृणमूल कांग्रेस ने उप चुनावों में

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 जुलाई। जहाँ इण्डिया गठबंधन विधानसभा उपचुनावों में अपने पार्टनरों की जीत की खुशियां मना रहा है, वहीं पश्चिम बंगाल की जमीनी स्थिति विपक्षी दलों के लिये बड़ी भयानक बनी हुई है।

विपक्ष के अधिकांश राजनेता एवं उम्मीदवार कह रहे हैं कि विधानसभा उपचुनाव वाले चारों विधानसभा क्षेत्रों में वैसी ही घिनौनी स्थिति है, जैसी लोकसभा चुनावों के दौरान थी।

तृणमूल कांग्रेस ने विपक्षी उम्मीदवारों को डराने-धमकाने, शारीरिक हिंसा की धमकियाँ देने, उन्हें एक स्थान तक सीमित कर देने जैसे हथकंडों का सहारा लिया था तथा सत्तारूढ़ दल की विजय के विगत परिणाम के लिये हर प्रकार के साधनों को काम में लिया था।

बाहुबल और हथियारों के ऐसे खूले प्रदर्शन तथा तिकड़मों के बाद भी, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने जोर देते हुए कहा था कि जनता ने उनकी पार्टी के पक्ष में मतदान किया है।

- सत्तारुढ़ पार्टी ने अपने फायदे के लिए सरकारी मशीनरी का जमकर दुरुपयोग किया बी.डी.ओ. व डी.एम. अधिकारियों का अपने हित में उपयोग करके
- इसका स्पष्ट उदाहरण था कि केन्द्रीय सरकार ने गंभीर हालात से निपटने के लिए जो क्विक रैस्पाँस टीम भेजी थी उसे राज्य पुलिस द्वारा घुमावदार रास्तों से गंतव्य स्थान पर ले जाया गया, और टीमें काफी देर से पहुंचीं।
- मतदान केन्द्रों पर तृणमूल के असामाजिक तत्व तैनात किए गए थे। लोगों ने विपक्षी नेताओं व कार्यकर्ताओं, जिसमें भाजपा भी शामिल है, को पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचने दिया।

सत्तारूढ़ दल ने अपने हितों को पूरा करने के लिए राज्य प्रशासन (जैसे बी.डी.ओ., डी.एम. तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों) के काम में लिया था। केन्द्र सरकार ने मतदान केन्द्रों तथा उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में आपातकालीन स्थितियों को सँभालने के लिये "क्विक रेस्पॉन्स" टीम (क्यू.आर.टी.) गठित की गई थी।

किन्तु इन क्यू.आर.टी. टीमों को उपद्रवग्रस्त स्थानों तक ले जाने का काम राज्य पुलिस ही करती थी। निरपवाद

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आवंटियों की सहमति के बिना बिल्डर ले-आउट प्लान नहीं बदल सकता

जयपुर, 13 जुलाई (का.सं.)। राजस्थान रियल एस्टेट अपीलीय प्राधिकरण ने एक प्रकरण में निर्णित किया कि बिल्डर आवंटियों की सहमति के बिना निर्माण शुदा इमारत के ले-आउट प्लान में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता। इसके अलावा संबंधित इमारत के ब्रॉशर में अंकित की गई सुख-सुविधा आवंटियों को मुहैया कराई जाएंगी, फिर चाहे उन्हें आवंटियों से निष्पादित किए गए इकरारनामे में दर्शाया गया हो या नहीं। प्राधिकरण ने यह आदेश साउथ एक्स रैजिडैंस वेलफेयर सोसायटी की अपील पर दिए।

- राजस्थान रियल एस्टेट एपिलेट ने एक केस में यह फैसला दिया और कहा कि बिल्डिंग ब्रोशर में अंकित सभी सुविधाएं आवंटियों को मुहैया कराई जानी चाहिए।

अपील में अधिवक्ता मोहित खंडेलवाल ने बताया कि बिल्डर विर्गो बिल्ड स्टेट ने सांगानेर में साउथ एक्स के नाम से एक आवासीय टाउनशिप वर्ष 2014 में शुरू की। जिसमें बिल्डर ने विला, फ्लैट और ग्रुप हाउसिंग बनाने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हिमाचल की जीत से कांग्रेस विशेष रूप से प्रसन्न है

मु.मंत्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू की खुशी का कारण है कि अब अन्य पार्टियों के विधायकों को तोड़ने का प्रयास करने वालों की कोशिशें अब बंद हो जायेंगी

-सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 जुलाई। सात राज्यों में हुए उपचुनावों में विपक्ष के इण्डिया गठबंधन को विधानसभा की 13 सीटों में से 10 पर विजय प्राप्त हुई है, सत्तारूढ़ भाजपा के साथ लोकसभा चुनाव में अपना मजबूत प्रदर्शन किया था, भाजपा जो पिछले माह केन्द्र में तीसरी बार लगातार सत्ता में आई है, उसे मात्र दो सीटें ही मिली हैं।

हिमाचल में एक उल्लेखनीय शुरुआत देखी गई, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू की पत्नी कमलेश ठाकुर को देहरा निर्वाचन क्षेत्र में विजय प्राप्त हुई। नलगढ़ सीट को भी जीतने से कांग्रेस की स्थिति मजबूत हुई है, जबकि भाजपा हमीरपुर की ही एक सीट को जीतने में सफल हो पाई है।

मुख्यमंत्री सुखू ने उपचुनावों में जीत के बाद अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा, हिमाचल की जनता ने उन लोगों को करारा जवाब दिया है जो लोग प्रदेश की "सरकार को गिराने का षडयंत्र रच रहे थे।"

सुखू ने कहा "हिमाचल की जनता ने 2022 के चुनावों में हमें 40 सीटें दी थीं। जनता ने अवैध रूप से सरकार गिराने वालों को सबक सिखाया है क्योंकि ऐसा प्रदेश की राजनीति में पूर्व में होता था।"

उन्होंने आगे यह भी कहा कि "इन चुनावों से यह भी संदेश जाता है कि प्रदेश की जनता सचेत व जागरूक है और अब ऐसी तोड़-फोड़ की योजनाएं सफल नहीं होंगी। तीन निर्दलीय विधायकों के पास इस्तीफा देने का कोई कारण नहीं था। वे सिर्फ फौरी तौर पर ही भाजपा से जुड़े थे परन्तु उनको भी सबक मिल गया।"

- मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रत्याशी धीरन शाह की हार ने अब फाइनल मोहर लगा दी, कांग्रेस के पूर्व मु.मंत्री कमलनाथ के राजनीतिक जीवन व प्रभाव के अन्त पर।
- बिहार में जे.डी. (यू.) की ओर से कई बार पूर्णिया सीट से विधायक बनीं बीमा भारती का किस्सा भी अजीबोगरीब है। उन्होंने, जे.डी. (यू.) से चुनी गई सीट से इस्तीफा देकर, आर.जे.डी. के उम्मीदवार के रूप में लोकसभा का चुनाव लड़ा था। पर, वे लोकसभा चुनाव में विजयी नहीं हुईं तो उन्होंने आर.जे.डी. की ओर से विधायक का चुनाव लड़ा पूर्णिया से, लेकिन इस बार वो चुनाव ही नहीं हारीं बल्कि तीसरे स्थान पर आयीं।

पंजाब में, आप पार्टी के मोहिन्दर भगत की जालंधर पश्चिम सीट से निर्णायक जीत हुई है, उन्होंने यह चुनाव 23,000 से अधिक वोटों के अन्तर से जीता है। इस बीच पश्चिम बंगाल में, टी.एम.सी. ने चारों सीटों पर लड़े गए चुनावों में अपनी जीत दर्ज करके पार्टी की धाक को बरकरार रखा है।

तमिलनाडु में द्रमुक के अनीपुर शिवा ने विधानसभा की विक्रावंडी सीट लगभग 60,000 वोटों के विशाल अन्तर से जीती है। उत्तराखण्ड में दोनों सीटों पर कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज की है, जबकि मध्यप्रदेश में अमरवाड़ सीट पर भाजपा के कमलेश प्रताप शाही विजयी हुए हैं और उन्होंने कांग्रेसी उम्मीदवार धीरन शाह इनावती को 3252 मतों के अन्तर से हराया है। इसे प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ युग के अंत रूप में देखा जा रहा है।

निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने बिहार में पूर्णिया की रूपौली विधानसभा सीट उपचुनाव में जीत ली है और जे.डी.ए. के कलाधर प्रसाद मण्डल को 8246 मतों के अन्तर से पराजित किया है। आर.जे.डी. की प्रत्याशी इस उपचुनाव में तीसरे स्थान पर रही हैं क्योंकि उन्हें 30,619 मत प्राप्त हुए हैं।

वर्तमान विधायक बीमा भारती के इस्तीफा देने की वजह से उप-चुनाव कराए गए थे, जो जे.डी.(यू.) की सीट से अनेक बार चुनाव जीत चुकी थीं

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

संविधान हत्या दिवस पर, प्रियंका ने सरकार को घेरा

नयी दिल्ली, 13 जुलाई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने 1975 में आपातकाल लगाने की तिथि, 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने के सरकार के फैसले पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि,

- कांग्रेस महासचिव प्रियंका ने आश्चर्य जताया कि जिन्होंने संविधान का सम्मान नहीं किया वो संविधान खत्म करना चाहते हैं, वे संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं।

जिन्होंने बार-बार संविधान पर प्रहार किया है वे नकारात्मक सोच के साथ संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं।

उन्होंने कहा कि जिन्होंने कभी संविधान को नहीं माना, संविधान लागू करने का विरोध किया, इसका कभी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'चीन के "एसैट्स" को नैशनलाइज़ करने के बारे में गंभीरता से विचार कर रहे हैं यूरोपीय देश

ये एसैट्स हैं, चीन द्वारा बैल्ट एण्ड रोड प्रोजैक्ट्स के तहत बनाए गए रेल मार्ग, बंदरगाह और हाईवे आदि

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 जुलाई। चीन को लेकर पश्चिमी देशों का संदेह इस हद तक पहुंच चुका है कि यूरोपीयन यूनियन यूरोप में एक बड़े संघर्ष के पूर्वानुमान के साथ अपने यहाँ स्थित चीन की इन्फ्रास्ट्रक्चर सम्पत्तियों के राष्ट्रीयकरण की संभावनाओं के बारे में सोच रही है।

पश्चिमी देशों के रक्षा संगठन "नाटो" की इस सप्ताह वॉशिंगटन में हुई एक मीटिंग में चीन को यूक्रेन में युद्ध छेड़ने के लिए रूस का सबसे बड़ा हमदर्द बताया गया। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनाइज़ेशन "नाटो" में आने वाले पश्चिमी देश यूक्रेन और आसपास के देशों में रूस के युद्ध अभियानों के आगे स्वयं को लगातार कमजोर महसूस कर रहे हैं।

चीन को लेकर यूरोपीयन यूनियन के रूख में बदलाव आया है। वह उत्साह के बाद पूर्ण संदेह में बदल गया है, जो भारतीय कूटनीति के लिए भी एक सबक है। रूस के साथ कैसा भी निकट संबंध अब पश्चिमी देशों के लिए संदेह का कारण है।

यूरोप में चीन के कई इन्फ्रास्ट्रक्चर और सम्पत्तियां हैं, जैसे कि रेलवे कनैक्शन्स, पोर्ट सुविधाएँ हाईवेज़ और बैल्ट एण्ड रोड इनिविएटिव के अन्तर्गत विकसित कई अन्य प्रोजैक्ट्स। नवीनतम रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोपीय देश अपने वहां मौजूद चीन की सम्पत्तियों का राष्ट्रीयकरण करने के बारे में सो रहे हैं और वे ऐसा करने के बाद ही अन्तर्राष्ट्रीय अदालतों में चीन की शिकायतों से निबटेंगे।

- अब चीन के खिलाफ उन्माद जैसी स्थिति है यूरोप में, कि इन इन्फ्रास्ट्रक्चरल प्रोजैक्ट्स को शत्रु सम्पत्ति की संज्ञा दी जा रही है।
- चीन को रूस का स्थायी मित्र माना जा रहा है और चीन के ये प्रोजैक्ट्स, जो सालों में धीरे-धीरे बने हैं, को नैशनलाइज़ करके यूरोपीय देश एक युद्ध जैसी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत शत्रु ही नहीं, शत्रु की मदद करने वाले मित्र राष्ट्र को भी शत्रु ही मान लिया जाता है।
- यूरोपीय देशों के मन में भय व्याप्त है कि रूस चीन की मदद से केवल यूक्रेन पर विजय पाकर संतुष्ट नहीं होगा तथा पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा और तब यूरोप के अन्य देश सुरक्षित नहीं रहेंगे तथा उन पर भी आक्रमण हो सकता है।

यूरोपीय देशों में चीन में इन्फ्रास्ट्रक्चर और सम्पत्तियों के निर्माण में बरसों लगे हैं। इसकी शुरुआत तब हुई जब वैश्विक आर्थिक मंदी और उसके बाद उपजे गतिरोध के बाद यूरोपीय देशों को ऐसा लगने लगा कि बड़ी आधारभूत परियोजनाओं के लिए चीन की फायनैंशियल क्रेडिट लाइन्स अधिक सस्ती और सुविधाजनक हैं, लेकिन रूस के साथ चीन की सम्बद्धता के बाद यूरोप में मौजूद चीन के प्रोजैक्ट्स को एक ऐसी अर्जित ताकत और संचालित सम्पत्तियों के रूप में देखा जा रहा है जो सुरक्षा को लेकर गंभीर चुनौती प्रस्तुत कर रही हैं।

इस बीच, रूस पश्चिमी देशों में मौजूद अपने गुप्त स्त्रोतों का पूर्ण उपयोग कर यूक्रेन को इन देशों की मदद ना मिलना सुनिश्चित कर रहा है। यूरोपीयन यूनियन के सदस्य देश युद्ध में घिरे यूक्रेन को अपना समर्थन पहले ही व्यक्त कर चुके हैं।

पश्चिमी यूरोप के देश रूस को लेकर भयभीत हैं और यूक्रेन में मिलने वाली रूस की किसी भी सफलता को उसके पश्चिमी यूरोप के दरवाजे पर आ

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नेपाल में के.पी. शर्मा ओली नए प्रधानमंत्री

काठमांडू, 13 जुलाई। नेपाल में पूर्व प्रधानमंत्री और सीपीएन-यूएमएल पार्टी के अध्यक्ष के. पी. शर्मा ओली ने देश में नयी सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत किया है और उन्हें रविवार को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलायी जाएगी।

निवर्तमान प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल की सरकार ने शुक्रवार को नेपाल की संसद का विश्वास मत खो दिया।

- रविवार को ओली को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी।

उसके बाद ओली ने नयी गठबंधन सरकार बनाने की अपनी दावेदारी पेश की है। नेपाल के समाचार माध्यमों की रिपोर्ट के अनुसार ओली को रविवार सुबह प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलायी जाएगी। काठमांडू से प्रकाशित अंग्रेजी अखबार 'माई रिपब्लिका' की आज की एक रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल कल आधिकारिक तौर पर ओली को प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे।